

ଶ୍ରୀମତୀ କୃପାଲୀ

वर्ष : 09 अंक : 80

प्रयागराज, मंगलवार 20 जून, 2023

हिन्दी दैनिक

ਪ੍ਰਾਚ—4

मूल्य : 3 रुपया

यूपी सरकार से ज्यादा नौकरियाँ मोदी सरकार ने दी : जितेंद्र सिंह



नई दिल्ली। बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार राजनीतिक हमलों का सामना कर रही मोदी सरकार की तरफ से पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि पिछले 9 सालों के दौरान मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में ज्यादा लोगों को नौकरियां दी है। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार के पहले 9 वर्ष के दौरान 6,02,045 भर्तियां की गईं। जबकि, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों के दौरान 8,82,191 भर्तियां की गईं। नौकरियों के गणित और गुणवत्ता, दोनों ही मामलों में मोदी सरकार, यूपीए सरकार की तुलना में कई गुना ज्यादा बेहतर रही है। केंद्रीय मंत्री ने नौकरियों के बारे में विस्तार से बताते हुए दावा किया कि यूपी सरकार के कार्यकाल में 2004 से 2013 के दौरान एसएससी द्वारा 2,07,563 भर्तियां की गई थीं। जबकि, मोदी सरकार के 9 वर्षों के दौरान 4,00,691 भर्तियां की गई हैं। इसी तरह से यूपी सरकार ने

पूरीएससी के द्वारा 45,431 नौकरियां दी थीं। जबकि, मोदी सरकार में यह अनेक बढ़कर 50,906 पहुंच गई। उन्होंने आगे कहा कि यूपीए सरकार आरआरबी के द्वारा 3,47,251 नौकरियां दी थीं। लेकिन, मोदी सरकार ने आरआरबी के जरिए इससे लगभग ज्यादा यानी 4,30,594 लोगों को नौकरियां दी हैं। इसके साथ ही नेंद्रीय मंत्री ने पेशन, कर्मचारियों की अमता वशद्धि, कर्मचारी कल्याण, एवं एस्टाचार मुक्त नियुक्ति प्रक्रिया, अच्छे

और ईमानदार कर्मचारियों को बढ़ावा देने और शिकायतों के उचित निवारण की व्यवस्था का दावा करते हुए यह भी यह भी जोड़ा कि भारत में ग्रीवांग सेल में जहां एक साल में पूरे देश में सिर्फ 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थीं। अब इसको कंप्यूटराइज्ड कार्पोरेशन पांच दिन के अंदर ही शिकायतों का निवारण करने की व्यवस्था बनाई गई है और इसकी वजह से आज सालाना देश भर से करीब 5 लाख तक शिकायतें दर्ज हो रही हैं। उन्होंने

स्टार्टअप्स से जुड़ी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को जागरूक किया कि रोजगार का अर्थ सिफ सरकारी नौकरी ही नहीं है और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज देश में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 1 लाख हो चुकी है। इसके साथ ही शरणमा मिशन के तहत 3 हजार एग्रीटेक स्टार्टअप भी शुरू हो चुके हैं।

**शिवराज सरकार अब
कर्मचारियों को खुश
करने की तैयारी में है**

भोपाल। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल भाजपा की शिवराज सरकार द्वारा हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। आधी आबादी और किसानों के लिए सरकार कई फैसले कर चुकी है। आने वाले दिनों में कर्मचारी वर्ग को खुश करना भी सरकार का लक्ष्य है। राज्य में कर्मचारियों और पेंशनर की संख्या पर गौर किया जाए तो यह संख्या लगभग 14 लाख के आसपास है। इनमें साड़े सात लाख नियमित कर्मचारी हैं तो साड़े चार लाख पेंशनर हैं, इसके अलावा सवा दो लाख संविदा कर्मचारी हैं। सरकार इन कर्मचारियों और पेंशनरों को खुश करने की रणनीति पर काम कर रही है। नियमित कर्मचारियों की जहां महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी है तो वही पेंशनरों की समस्या का भी निपटारा किया जाना है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात सरकार की ओर से दी जा सकती है। इस पर कर्मचारी कल्याण समिति के माध्यम से विचार-विमर्श जारी है। जानकारों की माने तो 14 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स और संविदा कर्मचारियों से जुड़े परिवार और उनसे जुड़े मतदाताओं की संख्या 60 लाख के आसपास पहुंच जाती है।

सुधाकरन को बदनाम करने पर माकपा नेता के खिलाफ कांग्रेस ने की केस दर्ज करने की मांग



कहा कि यह निर्दनीय है कि गोविंदन, जो पेशे से एक शिक्षक हैं, ने ऐसी घटिया बात कही, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। सुधाकरन ने कहा, मैंने बार-बार कहा है कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीपीएम के मुख्यपत्र की खबरों और गोविंदन के खिलाफ भी कानूनी सहारा लूँगा। उन्होंने कहा कि माकपा में अगर कोई नेता बचा है, तो उसे इस जघन्य कृत्य के खिलाफ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने मीडिया से कहा कि केरल पुलिस को पार्टी के मुख्यपत्र और गोविंदन के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। गोविंदन और देशभिमानी ने जो रिपोर्ट की है वह कोई मजाक नहीं है और यह केरल की राजनीति के इतिहास में एक ब्लैक डे के रूप में जाना जाएगा। यह बेल्ट के नीचे एक हिट है और सीपीआई (एम) राजनीतिक विरोधियों की छवि खराब करने में संलग्न है। सतीशन ने कहा, एक ओर अजीब बात यह है कि गोविंदन को पीड़िता द्वारा दिए गए 164 बयानों की सामग्री के बारे में कैसे पता चला और इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि अपराध शाखा पुलिस ने गोविंदन द्वारा कही गई बातों का खंडन किया है। हम यह देखने के लिए इंतजार करेंगे कि पुलिस इस मामले में क्या करती है।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਬੈਠਕ ਖਤਮ, ਗੁਰਦਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰण ਕੋ ਲੇਕਰ ਸੀਏਮ ਮਾਨ ਕਾ ਬਡਾ ਬਧਾਵ



चंडीगढ़। सी.एम. मान के नेतृत्व में आज कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट बैठक के बाद सी.एम. मान ने लाइव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहायक प्रोफेसर की पोर्टर्ट निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की आयु में 5 वर्ष की बढ़ातरी की गई है। उन्होंने कहा कि 37 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दी गई है। दूसरा फैसला उन्होंने पावर ऑफ अटार्नी को लेकर सुनाया है। उन्होंने कहा कि ब्लड रिलेशन वालों के लिए पावर ऑफ अटार्नी बिल्कुल फ्री की जाएगी जिसमें माता-पिता, दादा-दादी, बहन आएंगे जबकि ब्लड रिलेशन से बाहर वालों को पावर ऑफ अटार्नी के लिए 2 प्रतिशत फीस देनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सी.एम. मान ने गुरुबाणी प्रसारण को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा एक्ट 1925 में बारडकास्ट कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि एस.जी.पी.सी. पर एक ही परिवार का कब्जा है। गुरु की शिक्षा का प्रचार-प्रसार फ्री करना चाहिए। गुरुबाणी प्रचार फ्री टू एयर

यों नहीं होनी चाहिए। सी.एम. मान ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे मसंदां में गुरुद्वारे छुडवाए थे ऐसे ही मॉर्डन मसंदां से गुरबाणी छुडाएंगे। उन्होंने इसका कहा कि टेंडर पहले नहीं होते थे। बाब टेंडल बनाकर गुरबानी की बोली लगाई जाएगी। जो ज्यादा अमीर होगा वह ले जाएगा, फिर उसका चौनल लेगा और सारे घरों में उसे टेलीकॉस्ट केया जाएगा। 2012 में 11 वर्ष के लिए एसचखंड श्री दरबार साहिब से जो बाणी आती है उसके प्रसारण के प्रधिकार छीन लिए गए। सी.एम. मान ने कहा कि आपको बता देंकि जुलाई 2023 में गुरबाणी प्रसारण एग्रीमेंट खत्म हो रहा है बादलों के चौनल से। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इस बार कुछ नहीं किया गया तो एक बार फिर 10-11 साल तक फिर गहने रखा दिया जाएगा। सी.एम. मान कहा कि इसके लिए उन्होंने बड़े-बड़े वकीलों से बात की और सलाह-मशविर लिया। सी.एम. मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इंटरस्टेट नहीं बल्कि स्टेट एक्ट है। उन्होंने कहा कि अगर धारी साहब सुन रहे हैं तो सुनें फिर यह एक स्टेट एक्ट है। वह इसमें को संशोधन नहीं कर रहे और न ही को बदलाव कर रहे हैं। वह गुरबाणी प्रसारण किसी सरकारी अदारे को नहीं दे रहे।

की इस प्रारंभिक उत्तराधिकारी को आरंभिक तत्काल सुनवाई की मांग की। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश अरोड़ा ने बताया कि आदेश के खिलाफ अपील गत शुक्रवार को दायर की गयी थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उच्च न्यायालय ने 15 जून को आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए 48 घंटे के अंदर मांग की जाए और उनकी तैनाती की जाए। अदालत ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए 13 जून को उसके द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद से अब तक कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है।

केदारनाथ के गर्भगृह में भगवान शिवलिंग पर नोट फेंकती महिला का वीडियो वायरल, जांच के दिए आदेश



करीब सवा अरब रुपये का घोटाला होने के आरोपों को लेकर भी केदारनाथ मंदिर चर्चा में बना हुआ है जहाँ चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के साथ ही कंग्रेस और

गढ़वाल हिमालय में 11,760 फुट की उंचाई पर स्थित केदारनाथ दाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और रविवार तक 9,88,151 श्रद्धालु बाबा केदार

वार्षिक रथ यात्रा को लेकर पूरी में सारी तैयारियां पूरी



कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पेयजल पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जेना कहा कि अग्निशमन कर्मियों द्वारा उनीं का छिड़काव किया जाएगा, साथ में श्रद्धालुओं को ओआरएस के पैकेटों में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी नुष्ठानों को सुचारू रूप से करने के लिए आज शाम वरिष्ठ सेवादारों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं त्योहार को बाकर पुरी शहर और उसके आसपास रक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वीरथनगरी को 14 जून और 29 सेक्टरों पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा वहीं सोमवार को नबजौबन दर्शन के लिए कस्बे में 70 पुलिसकर्मियों को तैनाती की गई है। पहली बार एक तटरक्षक हेलीकॉप्टर समुद्र तट पर गश्त करेगा और पास में तेज गश्त वाहन तैनात किए जाएंगे। अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, संजय कुमार ने कहा कि इंटरसेप्टर नौकरी 2 जुलाई तक पारादीप में तैनात रहेंगी। वहीं रेलवे संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए प्लेटफॉर्म पर चेहरा पहचान

कुल 125 विशेष ट्रेनें पुरी के लिए चलेंगी। रथ यात्रा के दौरान कई कंट्रोल स्टेशनों से जुड़े ड्रोन कैमरों की सहायता से बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे काम करेंगे। यात्रा को देखते हुए पुरी में वाहनों की आवाजाही पर एक एडवाइजरी जारी की गई है। परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सभी अंतर्राजीय पर्यटक बसें और स्थानीय पर्यटक बसें मालतीपतपुर बस अड्डे पर रुकेंगी। अन्य दैनिक यात्रियों को ले जाने वाली बसों को मालतीपातपुर रेलवे ओवर ब्रिज, तोशाली रेत, ग्रिड स्टेशन चाक और भूदान छक्का से तलबानिया अस्थायी बस स्टैंड तक जाने की अनुमति दी जाएगी। वाहनों को भुवनेश्वर-पुरी मार्ग और कोणार्क मार्ग पर ग्रिड सबस्टेशन और तालाबनिया क्षेत्र के पास पार्क करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि ब्रह्मगिरि से आने वाले वाहनों को पलतोरेंस इंडिया गार्डन पार्किंग स्थल में पार्क किया जाएगा। शटल बसों और ऑटो रिक्शा को तालाबनिया से जिला स्कूल छक्का तक जाने की अनुमति होगी। वहीं दोपहिया वाहनों को जगन्नाथ बल्लव, मसनिचंडी, माटीटोटा नीलाचल अशोक और ब्लू पलैग बीच

का उपयोग किए जाने और इसमें समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक जा रहा भ्रम बताया है। इसी बीच, के दर्शन के लिए आ चुके हैं।

कोई भी हिंदू, मुस्लिम या कोई अन्य धर्मावलंबी हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए : सिद्धारमैया

बैंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि वह राज्य में अप्राकृतिक मौतों को कोई मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में सांप्रदायिक झड़पों के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य में साम्प्रदायिक झगड़ों में मारे गए छह पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपये के चेक वितरित करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कोई भी हिंदू, मुस्लिम या कोई अन्य धर्मावलंबी हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिस को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। किसी के पास कानून हाथ में लेने की ताकत नहीं है। मैं राज्य के लोगों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं। चाहे वे हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हों या बौद्ध हों, सभी को सरकार से सुरक्षा मिलेगी। सभी व्यक्तियों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा की जाएगी। कोई सवाल ही नहीं है। यही कारण है कि मुआवजे से वंचित रह गए पीड़ितों से बात की जाती है और मुआवजा दिया जाता है। चाहे वह मुस्लिम हो या हिंदू, सरकार को उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह लोगों का पैसा है। मारे गए प्रवीण कुमार नेतारू और हर्ष के परिवारों को तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा से 25 लाख रुपये का मुआवजा मिला। लेकिन, अन्य को नहीं दिए गए। सीएम ने कहा, मरने वाले सभी इंसान हैं। मशतकों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई प्रवीण कुमार नेतारू के घर गए थे, मोहम्मद फाजिल का घर करीब था, वह नहीं गए। उन्होंने आगे कहा कि प्रवीण और हर्ष के परिवारों को दिया गया मुआवजा सही है। लेकिन उन्हें दसरों के लिए भी मुआवजा देना होगा। उन्होंने कहा, सरकार अन्य मतक व्यक्तियों के परिवारों को रोजगार प्रदान करेगी।



भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं आदिपुरुष विवाद पर बोले अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। फिल्म आदिपुरुष पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आदिपुरुष में दिखाए गए संवादों पर हो रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार की ओर से भी सख्त टिप्पणी आई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी को भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म के लेखर और डायरेक्टर विवादित डायलॉग बदलने को तैयार हैं। आदिपुरुष शुक्रवार यानि 16 जून को रिलीज हुई थी। फिल्म में दिखाए गए संवादों को लेकर लोगों को आपत्ति है। इसी को लेकर फिल्म के खिलाफ देशभर में विरोध हो रहा है। फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग उठ रही है। फिल्म के डॉयलरों पर भारी विवाद हो रहा है। हनुमान जब लंका में जाते हैं, तो एक राक्षस उन्हें देखकर पूछता है, ये लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है, जो हवा खाने चला आया। वर्हीं जब माता सीता से मिलने के बाद हनुमान को जब लंका में राक्षस पकड़ लेते हैं, तो मेघनाथ उनकी पूँछ में आग लगाने के बाद पूछता है, जली। इसके जबाब में हनुमान कहते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। जब हनुमान लंका से लौटकर आते हैं और राम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? इसके जबाब में हनुमान कहते हैं— बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे, उनकी लंका लगा देंगे। बता दें कि फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई हैं। फिल्म के डायरेक्टर ओम राजत हैं।



सम्पादकीय

समान सहता का प्रश्न

निरसदह, भारत वावधाताओं का दश हा। वशवास, स्स्कृत व परपराओं का विविधता उसके मूल में रही है। गाहे-बगाहे देश में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठता रहा है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी जमकर होती रही है। भाजपा के एजेंडे में शामिल मुद्दे को कांग्रेस समेत कई दल धूवीकरण की कोशिशों के रूप में देखते रहे हैं। विधि आयोग की हालिया पहल ने इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। आयोग ने देश के हर नागरिक को इस बाबत अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान भी समान नागरिक संहिता का मुद्दा खासी चर्चा में रहा था। तब भरोसा जताया गया था कि इस लोकतांत्रिक देश में कालांतर में समान नागरिक संहिता लागू करने को मूर्त रूप देने का अवसर आएगा। दरअसल, तब संविधान सभा के कई दिग्गज इसके पक्ष में थे, लेकिन भारतीय समाज की जटिलता और तत्कालीन संवेदनशील स्थिति के चलते इस पर निर्णायक फैसला नहीं हो सका था। बाद में स्वतंत्र भारत में कई बार संसद व विधानसभाओं में इस मुद्दे पर खुब चर्चा होती रही। अब इसी कड़ी में व्यापक आधार रखने वाले धार्मिक संगठनों की इस मुद्दे पर राय मांगी गई है। दरअसल, इस जटिल विषय पर समान संहिता बनाना ही अंतिम हल नहीं है, उसका क्रियान्वयन भी उतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अलग-अलग धार्मिक समूहों को साथ लेकर आगे बढ़ना आसान भी नहीं होगा। फिर अगले साल होने वाले आम चुनाव व इस साल के अंत तक कई महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस मामले के सरगर्म रहने के आसार हैं। दरअसल, सवाल विधि आयोग द्वारा इस जटिल मुद्दे पर सार्वजनिक विमर्श को लेकर सिर्फ तीस दिन के समय को लेकर भी है। कुछ लोगों का मानना है कि सारे देश में व्यापक विमर्श के बाद ही इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे बात की जानी चाहिए। वैसे विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे को धूवीकरण के हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता है। इस क्यास की एक वजह यह है कि भाजपा के दो प्रमुख एजेंडे—राम मंदिर व अनुच्छेद 370 को हटाने के लक्ष्य हासिल किये जा चुके हैं। वर्ही देश में यह बहस पुरानी है कि व्यक्तिगत कानून में व्याप्त विसंगतियों को दूर करके एक देश, एक कानून की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाये। लेकिन धार्मिक रुद्धियों व राजनीतिक कारणों से ये लक्ष्य पाने संभव न हुए। वैसे किसी भी सभ्य समाज व लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों के लिये समान कानून के प्रावधान एक आदर्श स्थिति होती है। लेकिन भारतीय समाज की कई तरह की जटिलताएं इसके मार्ग में बाधक बनी रही हैं। निस्संदेह, देश की एकता व सद्भाव का वातावरण भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में कानून का निर्धारण धार्मिक आधार के बजाय तार्किक व समय की जरूरत के हिसाब से ही होना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि समाज में बहुमत व अल्पसमताओं के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

आतंकियों की शरणस्थली कबाड़ा



डायर जर म कहा गया ह क सभा
सातों गैंगस्टर्स ने छोटे समय के
अपराधियों के रूप में शुरुआत की
और समय के साथ कहरण्थी गैंगस्टर
बन गए। खालिस्तान समर्थक तत्व
कनाडा में रहकर भारत विरोध की
हदें पार कर रहे हैं। पिछले दिनों
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या
की झांकी निकालने की घटना ने
सभी हदें पार कर दी। जो बताती है
कि कनाडा में भारत विरोधी
वृथकतावादियों के हौसले कितने
बुलंद हैं और उन्हें सत्ता में शामिल

का सरकाण भिला हुआ हा-
न को हुई इस घटना का
सोशल मीडिया पर वायरल
बाद हर भारतीय राष्ट्रवादी
हुआ है। जिसके चलते भारत
ने भी घटना का कड़ा प्रतिवाद
। विदेश मंत्री एस. जयशंकर
शब्दों में कहा है कि ये घटना
भारत—कनाडा संबंधों के लिये
ही कनाडा के लिये ठीक है।
हने के लिये भारत में कनाडा
युक्त कैमरन मैक ने इस
निंदा की है और कहा है

पत्ता नारन का व्यापक रखा नारा
असी गतिविधियों को सहन नहीं कर
सकता। बेहतर यही होगा कि कनाडा
मपने कानूनों की समीक्षा करे और
देश से बाहर करने और उन्हें भरात
के हवाले करने के लिए ठोस कदम
उठाए। कनाडा के लिए स्पष्ट संदेश
कि वह अपनी जमीन पर भारत
विरोधी हरकतों पर रोक लगाए और
उन्हें नियंत्रित करे। उसे यह भी
रखना होगा कि हर तरह के अपराध
और आतंकवादी उसके यहां ही
यों छिपे बैठे हैं।—आदित्य नारायण

हिन्दू राष्ट्रवाद और अखंड भारत



रूप से निर्धारित हुईं और वे रियासतें जो अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रहीं भी अंग्रेजों की दया पर निर्भर थीं। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता से सांठ-गांठ कर राज किया। इन रियासतों को केवल औपचारिक रूप से सार्वभौमिकता हासिल थी। अंग्रेजों का राज स्थानांतर पर भी था, जो उनके साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक ऐसा ही सीलोन के मामले में भी था जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक सत्ता का कांग्रेस और भगतसिंह, अंडमान जेल जाने के पहले सावरकर और नेताजी सुभाष की आजाद हिन्दू फौज जैसी राष्ट्रवादी शक्तियों ने विरोध किया। अंग्रेजों ने फूट शक्तियों प्रबल हुईं जो एक-दूसरे के समानांतर परन्तु विपरीत थीं। गांधीजी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी शक्तियों का स्वन उस अखंड भारत का था, जो आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का क्षेत्र है। विभाजन की त्रासदी से राष्ट्रवादी शक्तियों का स्वप्न टूट गया और अंग्रेजों की देश को बांटने की साजिश सफल हुई। मुस्लिम साम्राज्यिक शक्तियों ने मांग की कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बने और हिन्दू साम्राज्यिक शक्तियां अखंड भारत पर अड़ी रहीं, जो उनके अनुसार चिरकाल से हिन्दू राष्ट्र था! जहां हिन्दू और मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने धर्म का सहारा लिया और दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ घुणा लगाया, वहां वे अपने धर्म का सहारा लिया और दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ घुणा लगाया।

उरुहरु हां पह नै रात्रि बवन क
उद्घाटन से भी प्रकट होता है जहां
अखंड भारत का एक भित्तिचित्र लगाया
गया है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भारत
ने हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।
मंसंसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने
ट्वीट कियारु शहमारा स्पष्ट संकल्प
अखंड भारत। जोशी ने कहा अखंड
भारत की अवधारणा प्राचीन भारतीय
संस्कृति से आई है। संसद का नया
बवन भारतीय संस्कृति के विभिन्न
हल्लों को दर्शाता है, जो भारत के
विभिन्न क्षेत्रों और उनके सभी आयामों
का प्रतिनिधित्व करता ह। एक अन्य
जापा नेता मनोज कोटक ने ट्वीट
किया नए संसद भवन में दर्शाया गया
अखंड भारत एक शक्तिशाली और
मात्रिभर भारत को दर्शाता है। भारत
सरकार के अधिकृत प्रवक्ता अर्द्दम
जागची ने कहा इस भित्तिचित्र में अशोक
का साम्राज्य दिखाया गया है और यह
उनके (अशोक) द्वारा अपनाई गई और
चारित उत्तरदायी और जनोन्मुखी
गासन की अवधारणा को दर्शाता है।
पाकिस्तान और नेपाल की सरकारों ने
जापा नेताओं द्वारा अखंड भारत की
बातें करने पर चिंता जाहिर की
है। यह काबिलेगौर है कि ये नेता चीन
द्वारा भारत की भूमि के एक बड़े टुकड़े
पर कब्जा जमाने पर चुप हैं। अखंड

था प्रकृत के बाच का एक सामजिक व्यापित करने वाला अद्भुत से सेतु था। और तब 11 दिसंबर 2014 को अन्युक्त राष्ट्र संघ में उसके 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नाने की सहमति देकर इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। इस प्रस्ताव द्वारा बहुत ही कम समय में मंजूरी प्रदान कर दी गई, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इतिहास की सबसे कम समय में दी गई मंजूरी थी। योग के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं। और हम यह यह सकते हैं कि योगाभ्यास ईश्वर द्वारा मानव सभ्यता को दिया गया एवं प्रतिम उपहार है। योग किसी अमत्कार से कम नहीं। जिन असाध्योमारियों का वर्तमान चिकित्सा पद्धति इलाज नहीं हो पाता, योग उन अमारियों को शनै शनै उपचार कर सकते कर देता है। यह शारीरिक

आज का राशफल

मध्य :- आज सावधाना बरतन का सलाह गणेशजी आपको देते हैं। संभव हो तो सरकार विरोधी कार्य से दूर रहिएगा। दुर्घटना से भी बचकर चलिएगा। बाहर के खानपान की आदत के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है। कार्य समयानुसार पूर्ण नहीं होंगे। व्यवसाय में भी संभलकर चलने की गणेशजी सलाह देते हैं।

वृषभ :- आपको रुचिकर मित्रों और अपने परिवार से लाभ होने की उम्मीद है।

स्वजना के साथ धूमने—फिरने से आनंद—उल्लास प्राप्त होगा। सुंदर वस्त्राभूषण और भोजन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, परंतु मध्याह्न के बाद स्वास्थ्य संभालने की ओर सावधानी बरतने की गणेशजी सलाह देते हैं। खर्च अधिक होगा।

मिथुन :- आपको रुचिकर मिठाँ और स्वजनाँ के साथ धूमने—फिरने से आनंद—उल्लास प्राप्त होगा। सुंदर वस्त्राभूषण और भोजन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, परंतु मध्याह्न के बाद स्वास्थ्य संभालने की ओर सावधानी बरतने की गणेशजी सलाह होते हैं। खर्च अधिक होगा।

धनु :- गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिकता के प्रति आपका अधिक आकर्षण रहेगा। गणेशजी के आशीर्वाद से आपको आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना है। नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए समय शुभ है। प्रियजनों के साथ मुलाकात होगी। विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। मध्याह्न के बाद स्थिति में बदलाव होगा।

कार्क :- गणेशजी कहते हैं कि भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए समय अधिक होगा।

मकरः— सामाजिक रूप से ख्याति प्राप्त होने से आज व्यावसायिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से

न कीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पारिवारिक समाज में आंति तरी चोरी।

वातावरण में शांति बना रहेगा।

सिंह :- आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। आर्थिक रूप से हानि हो सकती है। फिर भी मध्याह्न के बाद आप आर्थिक योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। परिश्रम के अनुरूप परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों को कार्य में सफलता प्राप्त होगी।

कन्या:- गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिकता के प्रति आपका अधिक आकर्षण रहेगा। गणेशजी के आशीर्वाद से आपको आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना है। नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए समय शुभ है। प्रियजनों के साथ मुलाकात होगी। विरेषियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। मध्याह्न के बाद स्थिति में बदलाव होगा।

दत्त है। स्वास्थ्य का सभालएगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिएगा। मानसिक रूप से भी कुछ अस्वस्थता का अनुभव होगा।

कुंभ :- आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और धनलाभ होने के संकेत गणेशजी आपको देते हैं। प्रत्येक कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होगा। कार्यालय में ऊपरी अधिकारी को आपके कार्य से संतोष रहेगा और पदोन्नति के योग हैं। मित्रों के साथ पर्यटन पर जाने का आयोजन भी हो सकता है।

मीन :- व्यवसायी और व्यापारीर्वर्ग के लिए प्रातरुकाल का समय अनुकूल नहीं है, ऐसा गणेशजी कहते हैं। ऊपरी अधिकारी तथा प्रतिस्पर्द्धियों के साथ व्यर्थ चर्चा या विवाद न करिएगा। कार्यालय का वातावरण अनुकूल होगा। अपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे।

ਤ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ह एकदम साफ कर दिया था। कर्मा और श्रीलंका जैसे देशों के सन्दर्भ में भारत की किसी तरह की आग्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं।

गारत ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और अपने पड़ोसी देशों से बूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये। इसी लग सकता है परन्तु यूरोपियन यूनियन इसका उदाहरण है कि किस प्रकार लम्बे समय तक एक—दूसरे से युद्धरत

देश में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एवं गंगा नदी पर्यावरण की स्थापना हुई और भारत ने इसकी गतिविधियों में उत्साह और भागीदारी की। सार्क के कारण रहे देश एक हो सकते हैं। आज पूरे यूरोप में एक मुद्रा और एक वीसा है। देशों की सीमाएं खुली हुई हैं और शिक्षा स्वारूप्य, पर्यटन और लगभग

क्षिण एशियाई देशों में संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में परस्पर बहयोग बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में बढ़ोत्तरी हुई। पीछे कुछ सालों से सार्क की गतिविधियां ठप हैं। क्या अखंड भारत का यह मतलब है कि भारत इन देशों पर हमला कर उन पर ब्याकरण कर लेगा और फिर दिल्ली में ठाठा बादशाह (जो पहली ही से बादशाही तरह व्यवहार कर रहा है) उन पर आसन करेगा? इस तरह का विस्तारवाद, केवल संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित देशों को शोभा देता है। डैटलर के राज में जर्मनी इसका एक बदाहरण है। राममनोहर लोहिया और नर्न्दर्म ने भारत और पाकिस्तान का हासंघ बनाने की बात कही थी। इस नर्न्दर्म में सार्क का अनुभव अत्यंत पाकारात्मक था परन्तु भारत में बढ़की आप्रदायिकता और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान, लालौंग, नार्मदा, गंगा और यमुना, विस्तारवादी तानाशाहों ने अपने और एक अन्य क्षेत्र में यूरोप के देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक बेहतर यूरोप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ समय से कतिपय महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के कारण दुनिया में उथल-पुथल जरूर मची हुई है। हमें अखंड भारत की जरूरत नहीं है। हमें क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है ताकि दक्षिण एशिया के देश अपनी—अपनी सरकारों को एकादिकारवादी प्रवश्तियों से मुक्त कर आम आदमी की जिन्दगी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकें। संसद में लगे भित्तिचित्र को अशोक के साम्राज्य के उच्चतर मूल्यों का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। अशोक का साम्राज्य जनकल्याणकारी था, विस्तारवादी नहीं। विस्तारवादी तानाशाहों ने अपने और अपने आसपास के देशों को बर्बाद करने और लाखों लोगों का खून बहाने के

